भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3741

16.03.2026 को उत्तर के लिए

बिहार में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3741. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जलवायु कार्य योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनके परिणाम क्या रहे;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) एनएपीसीसी के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) जलवायु-कार्य कार्यक्रमों के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में नौ मिशन शामिल हैं, जो सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारितंत्र, संधारणीय पर्यावास , हरित भारत, जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान तथा मानव स्वास्थ्य जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन मिशनों का कार्यान्वयन भारत सरकार की प्रासंगि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ हो साथ संबद्ध राज्यों के साथ अभिसरण में भारत सरकार के संबंधित नोडल मंत्रालयों और विभागों द्वारा, भारत सरकार की प्रासंगिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ समन्वय में तथा संबंधित राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार राज्य के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने में सहयोग प्रदान किया है। यह एसएपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुरूप तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एनएपीसीसी के एक मिशन जलवायु परिवर्तन पर सामरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी) के अंतर्गत बिहार में राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ (एससीसीसी) की स्थापना की है। राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ, बिहार राज्य को संवेदनशीलता और जोखिम आकलन करने, मानव क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने, जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने, संस्थागत क्षमता-निर्माण

करने तथा राज्य की राज्य कार्य योजना के अंतर्गत संधारणीय विकास के लिए चयनित कार्यों को लागू करने में सहायता प्रदान करता है। परियोजना के अंतर्गत जिला स्तर पर अध्ययन किए जाते हैं, जो एक कॉमन रूपरेखा का उपयोग करते हुए जलवायु अनुकूलन योजना तैयार करने में आगे उपयोगी हो सकते हैं।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की (एनपीसीसीएचएच) के अंतर्गत, जलवायु-संवेदनशील स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करने पर तंत्र विकसित किए गए हैं। बिहार सहित 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसीएचएच) तैयार की है, जिसमें प्रशिक्षण, परामर्शी/एडवाइजरी जारी करना, जागरूकता अभियान, निगरानी तंत्र विकसित करना तथा जिलों में सामुदायिक जागरूकता से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के एक मिशन, अर्थात संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के माध्यम से फसल खराब होने पर व्यापक बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि या क्षति झेलने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष के अंतर्गत भारत सरकार "बिहार में जलवायु स्मार्ट गाँवों को मुख्यधारा में शामिल करके जलवायु स्मार्ट कृषि का विस्तार" परियोजना को समर्थन दे रही है। यह परियोजना राज्य के आठ जिलों नामत: पटना, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर और दरभंगा में लागू की जा रही है।इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के लक्षित गाँवों में जलवायु सहनशील कृषि कार्यकलापों के पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करके ग्रामीण समुदाय की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना है। परियोजना की गतिविधियाँ किसानों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा प्रचलित जैव-भौतिक स्थितियों के अनुरूप जलवायु स्मार्ट कृषि कार्यकलापों से संबंधित हैं। साथ ही, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों के कार्यान्वयन और स्थायित्व के लिए हितधारकों की क्षमताओं को बढ़ाना तथा बेहतर ज्ञान प्रबंधन और साझाकरण के माध्यम से अनुकूलन रणनीतियों को नीतियों और कार्यक्रमों की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसे तेज़ी से विकसित करने के लिए कई उपाय और पहलें की हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जनजातीय समूह आवासों/गाँवों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम- जनमन) के अंतर्गत जनजातीय एवं विशेष रूप से कमजोर नई सौर ऊर्जा योजना तथा धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना जैसी योजनाएँ शुरू की गई हैं। सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए योजना लागू की जा रही है, जिसके

माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए डेवलपर्स को भूमि और ट्रांसमिशन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली के निकासी हेतु नई ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण और नए सब-स्टेशन क्षमता के सृजन को हरित ऊर्जा गलियारा योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किया गया है। इसके अलावा , सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल तथा ग्रिड से जुड़े सौर इन्वर्टरों के लिए मानकीकरण एवं लेबलिंग कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वनीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'जल-जीवन-हरियाली मिशन' लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार के इस मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान 38 जिलों में क्रमशः 414.90 लाख और 340.96 लाख पौधों का रोपण किया गया। जिला-वार वृक्षारोपण का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। इसके अलावा, इस मिशन के अंतर्गत 'मृदा नमी संरक्षण' कार्यों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान 17,661 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2,112 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किए गए। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान एसएमसी कार्यों के अंतर्गत क्रमशः 3,217 और 108 चेक डैमों का निर्माण किया गया।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत मिशनों की निगरानी एक बहु-स्तरीय संस्थागत ढाँचे के माध्यम से की जाती है। प्रत्येक मिशन किसी नोडल मंत्रालय के अधीन होता है, जिसमें अंतर्निहित निगरानी तंत्र शामिल होते हैं, जैसे संचालन समितियाँ, तकनीकी समीक्षाएँ तथा संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए परिणाम-आधारित संकेतक आदि, जिनके माध्यम से वित्तीय और भौतिक प्रगति की निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी समिति विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रगति की समीक्षा करती है और कार्यान्वयन से संबंधित बाधाओं का समाधान करती है। शीर्ष स्तर की नीतिगत मार्गदर्शन प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद (पीएमसीसीसी) द्वारा प्रदान किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति (एआईपीए) के माध्यम से प्रगति का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है।

****

अनुलग्नक-I

लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3741 के "बिहार में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव" के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को उत्तर के लिए संदर्भित **अनुलग्नक-I**

जिलेवार वृक्षारोपण रिपोर्ट (2024-25 और 2025-26)

क्रम संख्या	ज़िला	उपलब्धि (2024–25)	उपलब्धि (2025–26)
1	अररिया	867214	984281
2	किशनगंज	533030	580447
3	बांका	1433825	1870553
4	भागलपुर	945336	508006
5	जमुई	1435180	1563354
6	शेखपुरा	260589	274283
7	कटिहार	849681	407033
8	पूर्णिया	944003	891964
9	मधेपुरा	735407	617541
10	सहरसा	553828	534636
11	सुपौल	806310	951050
12	बेगूसराय	1095032	941895
13	खगरिया	528213	321460
14	गोपालगंज	939543	866048
15	सिवान	1424928	884972
16	दरभंगा	1257535	915682
17	मधुबनी	1633042	893986
18	पूर्वी चंपारण	1641784	1174431
19	तिरहुत	1798685	1075042
20	समस्तीपुर	1429940	1576330
21	सरन	1322554	916286
22	सीतामढ़ी	1218034	627963
23	शिवहर	257364	177423
24	वैशाली	1172001	795807
25	अरवल	331287	212320
26	औरंगाबाद	1381874	1407929
27	भोजपुर	878058	637475
28	बक्सर	606541	592875
29	गया	2938629	1775461
30	जहानाबाद	408722	330973
31	नालंदा	1045241	871785
32	नवादा	904532	1042626
33	पटना	1176299	612850
34	पश्चिमी चंपारण	1589712	1439036
35	रोहतास	1570793	1572925
36	कैमूर	1691729	1478974
37	मुंगेर	1253798	1417528
38	लखीसराय	630507	352857
कुल		**4,14,90,780**	**3,40,96,087**

****